

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट एवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 12 से 18 सितंबर 2026

भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित

वर्ष- 14

अंक-108

पृष्ठ- 8

मूल्य- रु.5/-

पीएम मोदी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का किया उद्घाटन

यूपीआई को वैश्विक बनाओ, फिनटेक अब क्रेडिट-बीमा-पेंशन तक बढ़े: चार सूत्रीय एजेंडा

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2026 का उद्घाटन किया। यह आयोजन 8 से 11 सितंबर तक था। इस वर्ष की थीम है “पोटेंशियल टू इम्पैक्ट: एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम”।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संघर्ष, ऊर्जा दबाव और व्यापार तनाव के बावजूद भारत ने अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। उन्होंने यूपीआई को भारत की फिनटेक कहानी का मुख्य स्तंभ बताया। अगस्त में अकेले 2,400 करोड़ से अधिक यूपीआई लेनदेन हुए। यूपीआई अब 11 देशों में सक्रिय है। अगला लक्ष्य इसे अन्य देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ना और प्रवासी भारतीयों के रেমिटेंस खर्च को कम करना है।

उन्होंने कहा कि फिनटेक अब केवल भुगतान तक सीमित न रहे। क्रेडिट, बीमा, बचत, निवेश और पेंशन का हिस्सा भी बढ़ना चाहिए। छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स तक औपचारिक वित्त पहुंचाने पर जोर दिया गया। पीएम स्वनिधि योजना 2030 तक बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने चार प्राथमिकताएं रखीं: उत्कृष्ट साइबर सुरक्षा, नैतिक डेटा संरक्षण मानक, नियामक-उद्योग नवाचार तंत्र और फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स, जिससे कंपनियों की पारदर्शी रेटिंग हो सके। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम जैसी तकनीकों को वास्तविक प्रभाव में बदलने की चुनौती भी बताई गई।

उन्होंने कहा कि भारत अब अपने वित्तीय मानक खुद बना सकता है। डिजिटल इंडिया की सफलता का अगला चरण समावेशी और भरोसेमंद वैश्विक वित्त प्रणाली है।



सीएम मोहन यादव दुबई में वैश्विक निवेश मिशन की अगुआई कर रहे हैं

जीआईएस 2027 से पहले यूएई में निवेशकों से संवाद, ओडीओपी-जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी

दुबई: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चार दिवसीय वैश्विक निवेश मिशन पर दुबई पहुंचे हैं। वे उच्चस्तरीय राज्य प्रतिनिधिमंडल के साथ एआईएम कांग्रेस 2026 में भाग ले रहे हैं और जनवरी 2027 में भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं।

विमानतल पर भारतीय प्रवासी समुदाय ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भारत के राजदूत दीपक मिश्र और महावाणिज्यदूत ई. विष्णु वर्धन रेड्डी से मुलाकात कर यूएई के सॉवरैन वेल्थ फंड, कॉर्पोरेट समूहों और संस्थागत निवेशकों से जोड़ने का आग्रह किया।

अरब संसद अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अल यामाही के साथ व्यापार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स और फूड प्रोसेसिंग पर चर्चा हुई। एआईएम कांग्रेस के टायकून्स डिनर में सॉवरैन फंड और वैश्विक कंपनियों से संवाद हुआ।

ताज दुबई में मध्य प्रदेश के ओडीओपी और जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इसमें बैतूल की घंटी धातु कला, चंदेरी-महेश्वरी साड़ियां, उज्जैन की बाटिक और ग्वालियर के कालीन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की रणनीति केवल पूंजी आकर्षित करना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक कारोबार के लिए भरोसेमंद मंच तैयार करना है। सिंगल विंडो, तेज मंजूरी और मध्य भारत की भौगोलिक स्थिति को लाभ बताया गया। अरब देशों के संसदीय नेताओं को भी जीआईएस 2027 का निमंत्रण दिया गया। यह दौरा प्रदेश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने का प्रयास है।



BNI
BHOPAL

BHOPAL IS GETTING ITS

MSME

CHAPTER.

BNI

MASTERS

Launching Soon

For Industrialists. For Manufacturers. For Growth.

FOR MORE DETAILS CONTACT US ON-
+91 83598 16434

RBI Approves ICICI Prudential AMC Stake of Up to 9.95% in AU Small Finance Bank

Nod Covers Mutual Fund Schemes, AIFs and PMS Clients; Subject to Banking Norms

New Delhi: The Reserve Bank of India has approved ICICI Prudential Asset Management Company's proposal to acquire an aggregate holding of up to 9.95 per cent in AU Small Finance Bank. AU Small Finance Bank said in a regulatory filing that it received the RBI approval letter dated September 8, 2026. The permission allows the asset manager to hold up to 9.95 per cent of the bank's paid-up share capital or voting rights. The approval covers ICICI Prudential AMC along with schemes of ICICI Prudential Mutual Fund, funds under alternative investment funds managed by the company and clients of its portfolio

management services. The holding must remain within the 9.95 per cent cap at all times and comply with the Banking Regulation Act, RBI directions on acquisition of shares or voting rights, FEMA rules and SEBI regulations. Such approvals are typically required when an investor's aggregate holding in a bank crosses prescribed thresholds. They do not by themselves mean an immediate purchase of the full stake. Any acquisition will depend on market conditions and internal investment decisions of the schemes and funds. The development reflects continued institutional interest in well-capitalised

small finance banks. AU Small Finance Bank has been expanding its retail and MSME franchise. For the asset manager, the nod provides flexibility to increase exposure across multiple investment vehicles without repeated regulatory filings, provided the combined holding stays within the approved limit.



सेबी ने जेपी मॉर्गन इकाई पर इंडेक्स हेरफेर मामले में प्रतिबंध हटाया अवैध लाभ जमा करने के बाद ट्रेडिंग बैन समाप्त, जांच जारी

मुंबई: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने जेपी मॉर्गन चेस की इकाई कॉर्पोरल मॉरीशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पर लगाया गया बाजार प्रतिबंध हटा दिया है। कंपनी ने कथित अवैध लाभ के रूप में 2.96 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। सेबी ने 13 अगस्त को बीएसई के क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में सेसेक्स से जुड़े ट्रेड्स को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया था। आरोप था कि कॉर्पोरल और मुंबई की ब्रोकरेज मंसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग ने समापन नीलामी में बड़े ऑर्डर लगाकर और रद्द कर इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस प्रभावित किया। इससे उनके एक्सपायरी वाले ऑप्शंस पोजिशन को फायदा हुआ। सेबी ने कुल करीब 3.68 करोड़ रुपये के कथित लाभ जब्त करने का आदेश दिया था, जिसमें मंसी का

हिस्सा भी शामिल है। आदेश में कहा गया था कि लाभ जमा होते ही ट्रेडिंग प्रतिबंध हट सकता है। दोनों संस्थाओं ने राशि जमा कर दी, जिसके बाद उन्हें भारतीय पूंजी बाजार में कारोबार की अनुमति मिल गई। हालांकि बाजार हेरफेर की जांच जारी रहेगी। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन शेयरों के समापन मूल्य तय करने की नई व्यवस्था है। सेबी का यह कदम इस तंत्र के दुरुपयोग पर सख्त नजर का संकेत माना जा रहा है। कॉर्पोरल जेपी मॉर्गन इंडिया की ब्रोकर इकाई से अलग मॉरीशस पंजीकृत इकाई है। अंतिम आदेश जांच पूरी होने के बाद आएगा।



भारत का क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात केवल 53-55 प्रतिशत: नीति आयोग यूपीआई डेटा से एमएसएमई ऋण बढ़े, औपचारिक लेंडिंग अभी संकरी: अशोक लाहिड़ी

मुंबई: नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने कहा है कि भारत का क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात मात्र 53-55 प्रतिशत है, जबकि विकसित देशों में यह 150-170 प्रतिशत तक है। औपचारिक ऋण आधार अभी संकरा है, खासकर सूक्ष्म इकाइयों और एमएसएमई के लिए। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में उन्होंने सुझाव दिया कि बैंक और फिनटेक कंपनियां यूपीआई लेनदेन डेटा का उपयोग कर क्रेडिट मूल्यांकन और जोखिम आकलन बेहतर बनाएं। इससे छोटे उद्यम औपचारिक ऋण प्रणाली में आ सकेंगे। लाहिड़ी ने कहा कि बैंकों के एनपीए कम हैं, फिर भी वे सतर्क ऋण नीति अपना रहे हैं। गुणवत्ता बनाए रखते हुए साख योग्य उधारकर्ताओं को और ऋण देने की गुंजाइश है। भारत में निवेश जीडीपी का 30-34 प्रतिशत है, जो चीन और कोरिया से करीब 10 प्रतिशत अंक कम है। विनिर्माण का हिस्सा बढ़ा है, लेकिन पैमाना अभी प्रतिस्पर्धियों जितना नहीं है। उन्होंने घरेलू बचत से निवेश वित्तपोषण, निर्यात मांग और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के लिए एफडीआई पर जोर दिया। कौशल विकास में सरकार-उद्योग सहयोग और अप्रेंटिसशिप मॉडल की जरूरत बताई। बुनियादी ढांचे के लिए पीपीपी और दीर्घकालिक जोखिम पूंजी का सुझाव दिया गया। वर्तमान खाता घाटा एक प्रतिशत से नीचे रहने और आगामी अधिशेष की संभावना के बीच भारत की वृद्धि फिर गति पकड़ सकती है। यूपीआई डेटा का ऋण में उपयोग वित्तीय समावेशन का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है।



MP Courts \$1 Billion Private Capital for Solar-and-Storage Push with ADB

First ADB transaction advisory mandate in India to structure three PPP clean-energy projects; Shajapur plant to pair solar with batteries for peak demand

भोपाल: Madhya Pradesh has signed an agreement with the Asian Development Bank to structure three renewable-energy projects through public-private partnerships, an initiative expected to attract up to \$1 billion in private investment. The pact was signed in Bhopal by ADB Country Director for India Mio Oka in the presence of Chief Minister Mohan Yadav and marks ADB's first transaction advisory services mandate in the country.

ADB will advise the state on preparing, structuring and procuring the projects so that tenders are commercially viable and bankable. One project in the pipeline is a solar generation and battery energy storage facility at Shajapur, designed to meet peak electricity demand and support grid stability. Batteries would store solar power generated during the

day and supply it in the evening and at other hours when sunlight is unavailable, improving reliability for local distribution networks.

The projects align with the Madhya Pradesh Renewable Energy Policy 2025, which aims to expand generation and storage so that renewables meet 50% of the state's electricity demand by 2030. Storage is central to that goal. Solar output varies through the day and drops after sunset, while household and industrial demand often peaks in the evening. Combining generation with storage turns intermittent supply into dispatchable power.

Oka said public resources alone cannot meet India's growing energy needs and that private capital exists but markets must be made investable. By structuring bankable PPP projects, ADB hopes to

crowd in private investment, demonstrate workable models and create templates that can be scaled across the state. The bank will draw on its experience in project preparation and procurement across Asia and the Pacific. ADB has worked with Madhya Pradesh for more than 25 years on development and energy infrastructure; this agreement extends that relationship into transaction advisory for clean-energy PPPs.

For investors, the package is less a single plant and more a framework: clear contracts, peak-demand design and a policy target that treats storage as part of the grid, not an add-on. Success will depend on tariff design, offtake certainty and timely procurement. If the first tenders close well, Madhya Pradesh could become a reference market for solar-plus-storage PPPs in central India.


SUNDARAM MUTUAL
 Sundaram Finance Group

Stay on track with Midcap Funds

Invest where momentum meets potential

Midcap companies represent the next generation of market leaders
Agile, Ambitious, and Built for Growth

Tap into this potential through Mid Cap Funds that aim to balance opportunity and resilience

Learn More

An investor education initiative by Sundaram Mutual

Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



WE ARE HIRING!

BUSINESS GROWTH MANAGER

Join our dynamic team and be a part of a **growing legacy**.

EXPERIENCE
3-5 Years

QUALIFICATION
MBA / MJMC

CTC
3-5 Lacs per annum

WHY JOIN US?

- Be part of a trusted brand in financial journalism
- Work in a dynamic and growth-oriented environment
- Excellent learning and growth opportunities
- Performance based rewards

APPLY NOW

SEND RESUME TO
editor@investmentavenues.in

CONTACT NO.
9238363255

WEBSITE
www.investmentavenues.in

ADDRESS
 E4 Aera Colony, Dutt Mandir Campus,
 Bhopal-462016

Built Your Career in your Industry

MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES
 (इन्वेस्टमेंट एवेन्यू)
 (A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

YOUR DAILY GUIDE TO STOCK MARKET & BUSINESS NEWS

मध्य प्रदेश ने भव्य योजना के तहत 11 औद्योगिक पार्कों का प्रस्ताव रखा
 ₹8,144 करोड़ की लागत, 9,000 एकड़ से अधिक भूमि पर
 गैर-अपेक्षित सुविधाएं

प्रधानमंत्री मोदी के 'शक्ति की सुधार' विजन को साकार करने का संकेत: शिवराज सिंह चौहान

Cabinet Clears ₹13,041 Crore Rail and Road Projects

कमजोर मानसून से बड़ी खाद्य महंगाई, लेकिन ग्रामीण भाग मजबूत: नोमुरा

TRUSTED NEWS | SHARP INSIGHTS | SMART DECISIONS | BETTER TOMORROW

Motilal Oswal Pours ₹600 Crore into KARAM Safety for Global Push

IBEF V's fifth bet backs India's largest fall-protection and PPE maker as it hunts acquisitions across products and markets

Mumbai: KARAM Safety Private Limited has raised ₹600 crore from Motilal Oswal Alternates to fund acquisitions and international expansion. The investment comes through India Business Excellence Fund V (IBEF V), which closed at ₹8,500 crore in February 2026. KARAM is the fund's fifth portfolio company.

Founded in 1998, KARAM is India's largest player in fall protection and personal protective equipment, with more than 3,800 products including harnesses, lanyards, helmets, safety footwear, and respiratory, hearing and hand protection. It sells under four global brands across the United States, Europe, South America, Africa and Asia Pacific.

The capital will support inorganic growth and diversification, with a focus on acquisitions in complementary product categories, technologies and overseas markets. The company also plans to strengthen manufacturing, product

innovation and its global distribution network. Hemant Sapra, co-founder and president of global sales and marketing, said the money gives KARAM the flexibility to enter new categories and markets and to accelerate its aim of becoming a global safety-industry leader. Prakash Bagla, managing director for manufacturing at Motilal Oswal Alternates, said India is emerging as a hub for high-quality safety and industrial products, and that KARAM is among the few homegrown brands with genuine depth in research, manufacturing and international distribution. Motilal Oswal Alternates manages about ₹30,000 crore across private equity, real estate and private credit. Its private equity arm, set up in 2006, manages ₹18,000 crore across five funds and backs mid-market companies in consumer, financial services, life sciences and niche manufacturing.

Demand for occupational safety gear is rising with infrastructure, manufacturing and stricter workplace standards at home and abroad. For investors, the deal is a bet on a profitable Indian manufacturer that already has export reach and can use private equity to scale faster through acquisitions rather than organic growth alone. Execution on targets, integration and brand positioning against global rivals will decide whether KARAM converts this cheque into a larger international franchise.



टोरेंट ग्रीन एनर्जी ने नासिक में 322 मेगावाट विकेंद्रीकृत सौर परियोजनाएं चालू कीं 3,000 तक

MSKVY 2.0 और पीएम-कुसुम के तहत 50 स्थलों पर प्लांट; MSSEDCL से 25 वर्ष का बिजली खरीद समझौता

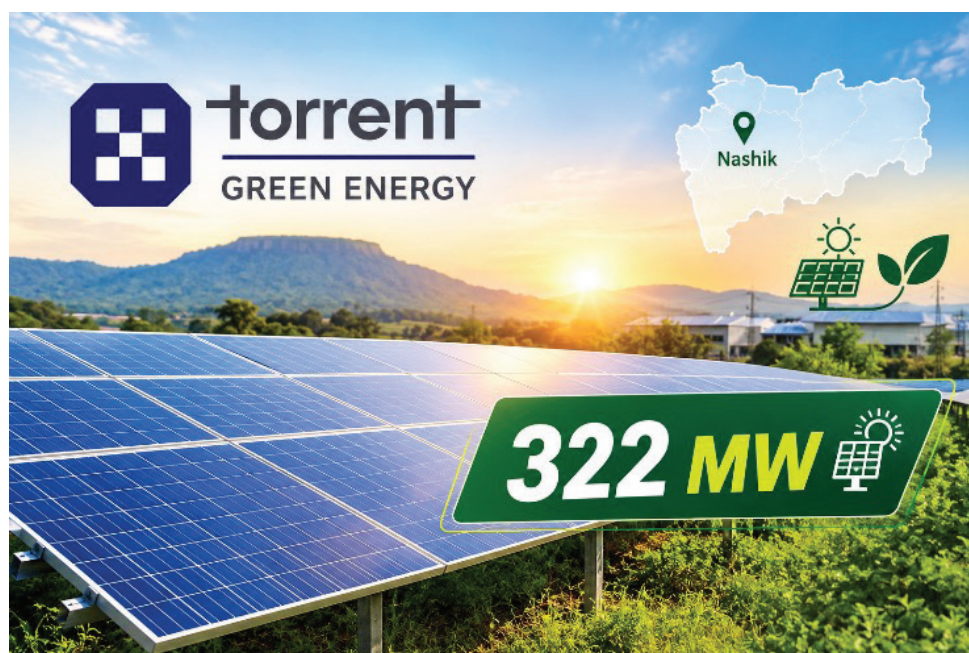
भिंड: टोरेंट पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक टोरेंट ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में 322 मेगावाट पीक क्षमता की भूमि पर आधारित विकेंद्रीकृत सौर परियोजनाएं चालू कर दी हैं। ये परियोजनाएं मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना (MSKVY) 2.0 के अंतर्गत बनी हैं, जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) की घटक-सी के तहत कृषि फीडर सोलराइजेशन का हिस्सा है।

पोर्टफोलियो 50 स्थलों पर फैला है और नासिक की 14 तहसीलों को कवर करता है। कंपनी के अनुसार यह एमएसकेवीवाई ढांचे के तहत सबसे विस्तृत और भौगोलिक रूप से विविध कृषि फीडर सोलराइजेशन परियोजनाओं में से एक है। उत्पन्न बिजली महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसडीसीएल) को 25 वर्ष के बिजली खरीद समझौते के तहत दी जाएगी।

उद्देश्य कृषि मांग केंद्रों के निकट स्वच्छ ऊर्जा पैदा करना है, ताकि ग्रामीण फीडरों को दिन के समय बिजली मिल सके। इससे किसानों को रात के बजाय दिन में आपूर्ति मिलने, ग्रिड दक्षता सुधरने और वितरण हानियों के घटने की उम्मीद है। टोरेंट पावर के होल-टाइम डायरेक्टर जिगीष मेहता ने कहा कि यह उपलब्धि एमएसडीसीएल, स्थानीय प्रशासन, भूस्वामियों, ठेकेदारों और कंपनी की टीम के सहयोग का परिणाम है तथा कृषि क्षेत्र को विश्वसनीय दिन की बिजली देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

50 अलग-अलग स्थलों पर निर्माण आसान नहीं था। प्रत्येक स्थान पर भूमि, ग्रिड कनेक्टिविटी और स्थानीय मंजूरीयें जुटानी पड़ीं तथा कई जगह एक साथ काम चलाया गया। टोरेंट पावर की कुल परिचालन उत्पादन क्षमता करीब 6.66 गीगावाट है, जिसमें लगभग 2.2 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता शामिल है। निर्माणाधीन नवीकरणीय परियोजनाएं और भी बढ़ी हैं।

निवेशकों के लिए यह परियोजना दीर्घकालिक, अनुबंधित राजस्व का अवसर प्रस्तुत करती है। राज्य-समर्थित बिजली खरीद व्यवस्था (ऑफटेक) से मांग और भुगतान से जुड़ा जोखिम कम होता है, जबकि विकेंद्रीकृत मॉडल बड़े एकल बिजली संयंत्रों की तुलना में बिजली को उपभोक्ताओं और कृषि क्षेत्रों के अधिक करीब पहुंचाता है।



कृषि सोलराइजेशन भारत की स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि इन परियोजनाओं का संचालन सफल रहता है, तो इन्हें अन्य जिलों में भी अपनाए जाने योग्य मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

Empower India Bets on Green Data Centres to Ride India's AI Compute Wave

Company plans custom Green Data Servers as India AI Mission and GPU rollout lift demand for power, cooling and high-density infrastructure

Mumbai: Empower India says it is positioned to benefit from the rapid build-out of India's artificial intelligence computing ecosystem through a push into sustainable digital infrastructure. The company points to the expansion of national AI compute capacity under the Rs 10,372 crore India AI Mission and rising GPU deployment as drivers of demand for energy-efficient data centres, high-performance computing, advanced cooling and reliable power systems.

The India AI Mission, announced in 2024, is meant to accelerate computing capacity, data infrastructure and AI applications. Empower India argues that this shift will increase the need for facilities that can run modern, heat-intensive workloads around the clock. Growth, it says, will come from energy-efficient data-centre infrastructure, power optimisation for continuous uptime, thermal-management solutions for dense hardware, and sustainable systems aligned with green-energy goals.

The company has expanded into

customised Green Data Server and data-centre offerings, focusing on tailored infrastructure, energy-efficient operations and intelligent facility management. The move builds on its existing work in sustainable power solutions and network infrastructure, and on the renewable-energy capabilities of subsidiary Empower Energy. Managing Director Rajesh Chavan has earlier described technology infrastructure and sustainable energy as interconnected pillars of a data-driven economy.

India's data-centre market is widely projected to grow sharply this decade as AI, cloud computing, enterprise digitisation and data-localisation rules raise domestic demand. Industry estimates put operational capacity well above 1 GW already, with several more gigawatts under development. AI training and inference consume far more power and cooling than conventional cloud loads, so operators need both cheap, reliable electricity and efficient thermal design.

Empower India reported revenue of Rs 37.38 crore for the June quarter of FY26,

up about 41%, and net profit of Rs 1.49 crore. Those figures remain small relative to the scale of the national AI and data-centre build-out. For investors, the story is a small listed player trying to attach itself to a large policy-and-capex cycle. Execution on green-server products, power reliability and customer wins will matter more than the slogan. If India AI spending and GPU installations continue, demand for efficient, high-density infrastructure should stay firm—but competition from established data-centre operators will be intense



श्रीराम जनरल इश्योरेंस और एसके फाइनेंस का समझौता, 700 से अधिक शाखाओं से बीमा वितरण

कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी से ग्रामीण-अर्धशहरी ग्राहकों तक जनरल इश्योरेंस पहुंचाने का लक्ष्य; दावे श्रीराम संभालेगी

नई दिल्ली: श्रीराम जनरल इश्योरेंस (एसजीआई) ने एनबीएफसी एसके फाइनेंस के साथ बीमा उत्पादों के वितरण के लिए रणनीतिक कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी की घोषणा की है। संयुक्त बयान के अनुसार उद्देश्य प्रमुख बाजारों में बीमा समाधानों तक पहुंच बढ़ाना और ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

इस समझौते के तहत एसजीआई अपने जनरल इश्योरेंस उत्पाद एसके फाइनेंस के 700 से अधिक शाखा नेटवर्क और अन्य निर्धारित वितरण माध्यमों से पेश करेगी। ग्राहक वित्त कंपनी के नेटवर्क से उपयुक्त पॉलिसी ले सकेंगे, जबकि दावे और सर्विसिंग एसजीआई के स्थापित तंत्र से होंगे।

एसके फाइनेंस करीब 31 वर्ष पुरानी एनबीएफसी है और ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में वाहन व अन्य वित्त में मजबूत उपस्थिति रखती है। प्रबंध निदेशक और सीईओ राजेंद्र कुमार सेतिया ने कहा कि बीमा वित्तीय लचीलापन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर उन ग्राहकों के लिए

जिन तक व्यापक सुरक्षा समाधान आसानी से नहीं पहुंचते। श्रीराम जनरल इश्योरेंस के साथ साझेदारी वित्त पारिस्थितिकी से बीमा को जोड़ने और उभरते बाजारों में पहुंच बढ़ाने का कदम है। कंपनी तकनीक में भी निवेश कर रही है।

एसजीआई के कार्यकारी निदेशक और सीएमओ आफताब अलवी ने कहा कि एसके फाइनेंस की पहुंच और बाजार उपस्थिति के साथ कंपनी की ग्राहक-केंद्रित शैली को जोड़कर अधिक लोगों तक बीमा जागरूकता और उत्पाद पहुंचाने का लक्ष्य है।

एनबीएफसी-बीमा साझेदारियां भारत में बैंकाश्योरेंस के बाद वितरण का बड़ा माध्यम बन रही हैं। ऋण ग्राहक के पास पहले से संबंध होता है, इसलिए मोटर, संपत्ति और व्यक्तिगत दुर्घटना जैसी पॉलिसी बेचना अपेक्षाकृत आसान होता है। सफलता शाखा कर्मियों के प्रशिक्षण, सही उत्पाद मैपिंग और दावों में तेजी पर निर्भर करेगी। गलत बिक्री या सर्विस में देरी से ब्रांड दोनों तरफ प्रभावित हो सकता है।

निवेशकों के लिए यह सौदा एसजीआई की वितरण क्षमता बढ़ाने और एसके फाइनेंस की फीस आय बढ़ाने वाला है। भारत में बीमा घनत्व अभी भी कम है। यदि साझेदारी ग्रामीण-अर्धशहरी ग्राहकों तक सही कवरेज पहुंचाती है तो दोनों कंपनियों के लिए यह सतत राजस्व का स्रोत बन सकती है।



इनॉक्स विंड को इंडियन ऑयल से मिला ₹755 करोड़ का टर्नकी ऑर्डर 100 मेगावाट पवन परियोजना में टर्बाइन सप्लाई, ईपीसी और दीर्घकालिक ओ एंड एम शामिल

नई दिल्ली: इनॉक्स विंड को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 100 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना का टर्नकी ऑर्डर मिला है। सौदे की वैल्यू करीब ₹755 करोड़ है। कंपनी टर्बाइन जनरेटर की आपूर्ति, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन तथा परियोजना निष्पादन का पूरा काम करेगी। कमीशनिंग के बाद दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव सेवाएं भी इसी करार में शामिल हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ओ एंड एम अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है। इनॉक्सजीएफएल ग्रुप के रिन्यूएबल्स सीईओ कैलाश ताराचंदानी ने कहा कि महारत्न कंपनी और देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी से यह ऑर्डर मिलना महत्वपूर्ण है। इससे इनॉक्स विंड की पूरी परियोजना चक्र संभालने की क्षमता मजबूत होती है टर्बाइन सप्लाई से लेकर ईपीसी और ओ एंड एम तक। यह ऑर्डर कंपनी के ग्राहक आधार को और विविध बनाता है, जिसमें वाणिज्यिक-औद्योगिक उपभोक्ता, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और स्वतंत्र बिजली उत्पादक शामिल हैं। इंडियन ऑयल पहले भी इनॉक्स से जुड़ी रही है, इसलिए यह दोहराया गया विश्वास माना जा रहा है। तेल कंपनियां अब नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ा रही हैं। ऐसे टर्नकी सौदे पवन उपकरण निर्माताओं के ऑर्डर बुक को सहारा देते हैं और ऊर्जा मिश्रण में हरित हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करते हैं। परियोजना स्थल का आधिकारिक ब्योरा कंपनी ने अलग से नहीं दिया है।



Biocon Signs 10-Year Brazil Supply Deal for Pertuzumab Breast Cancer Drug

MoU Covers Buildings, Allied Works and Project Management Consultancy

Bengaluru: Biocon has signed a 10-year supply contract for Pertuzumab, a monoclonal antibody used to treat HER2-positive breast cancer, as part of a consortium with Brazil's Bahiafarma and Bionovis.

The consortium received 100 per cent allocation under Brazil's Productive Development Partnership programme, giving it exclusive access to the public healthcare market. Brazil's Unified Health System accounts for about 70 per cent of the country's Pertuzumab demand. The drug is not manufactured locally and is a major cost for the public system.

Biocon will receive milestone payments and a share of revenues from the PDP opportunity over 10 years. The arrangement is designed to improve access to the therapy and support phased localisation of production in Brazil.

CEO and Managing Director Shreehas Tambe said Brazil is an important market for Biocon and that the contract would help reach more patients with HER2-positive breast cancer. He said the partnership combines science, manufacturing and local expertise to create a more sustainable supply pathway.

Bahiafarma CEO Ceuci Nunes said the project would help Brazil strengthen its capacity to produce essential medicines for the public system.

The deal expands Biocon's Latin American footprint in oncology biologics. For Brazil, it is part of a policy to reduce import dependence on complex cancer drugs. Commercial volumes and the pace of technology transfer will determine how quickly local manufacturing comes on stream. The agreement underlines growing South-South partnerships in affordable biologics.



Craft Whiskey Startup Marmalade Raises ₹6 Crore from Angel Investors

Brightside Brand Hits ₹5 Crore Annualised Run Rate; Funds to Expand Maharashtra Distribution

Mumbai: Alco-bev startup Marmalade, the company behind craft whiskey brand Brightside, has raised ₹6 crore from about 20 angel investors in an early-stage round. The investors include operators and founders from drinks and consumer businesses, among them Amrut Distilleries chief operating officer Ashok Chokalingam, Don Q Rum family member Robert Sellares, former AB InBev director Ishank Gupta, Malt Society Arabia founders, and HomeLane founders Srikanth Iyer and Tanuj Choudhry. Marmalade was co-founded by Udit

Mediratta, previously chief marketing officer at HomeLane and a director at AB InBev, and investment banker Surojit Bhattacharya. Brightside was launched in Pune in January 2026 and is now entering Mumbai. The company said it is on track for a ₹5 crore annualised revenue run rate and is targeting further growth in the two cities.

The brand is positioned as a smoother, more approachable whiskey for younger legal-drinking-age consumers. Funds will be used to expand distribution in key whiskey-consuming states, strengthen

branding, and build sales and operations. India is among the world's largest whiskey markets, but much of the volume is still in mass IMFL. A new wave of craft and premium Indian labels is trying to occupy the mid-premium shelf. State-wise licensing, excise rules and distribution remain the main constraints for any new spirit's brand.

Marmalade's challenge will be to convert early Pune traction into a wider retail footprint without losing brand distinctiveness as it scales.

गैलेक्सआई को सैटेलाइट इमेजिंग तकनीक का अमेरिकी पेटेंट मिला

ऑप्टिकल एसएआर से बादल और अंधेरे में भी पृथ्वी का चित्र, पहली भारतीय स्पेस स्टार्टअप

बेंगलुरु: भारतीय स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सआई को सैटेलाइट इमेजिंग तकनीक के लिए अमेरिकी पेटेंट मिल गया है। कंपनी का दावा है कि वह इस क्षेत्र में अमेरिकी पेटेंट पाने वाली पहली भारतीय स्टार्टअप है। यही तकनीक भारत में पहले पेटेंट हो चुकी है।

पेटेंट एक ऐसी प्रणाली से संबंधित है, जो ऑप्टिकल और रडार (SAR) सेंसर को एक ही उपग्रह पर समन्वित एवं सिंक्रोनाइज़ करके संचालित करने में सक्षम बनाती है। इससे एक ही स्थान की तस्वीरें एक ही समय पर सटीक संरेखण के साथ ली जा सकती हैं। सामान्यतः दोनों सेंसर अलग

उपग्रहों या अलग समय पर काम करते हैं, जिससे तुलना कठिन हो जाती है। एसएआर बादल और रात में भी काम करता है, जबकि ऑप्टिकल सेंसर रंग और स्पेक्ट्रल जानकारी देता है।

संस्थापक और सीईओ सुयश सिंह ने कहा कि यह तकनीक मौसम से अप्रभावित इमेजिंग देगी और रक्षा, कृषि, बीमा तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाएगी। गैलेक्सआई आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों द्वारा स्थापित है और करीब 21 मिलियन डॉलर जुटा चुकी है। कंपनी पांच वर्षों में 30 उपग्रहों का

तारामंडल बनाने की योजना रखती है। अगस्त में उसने बेंगलुरु की स्टारऑप्स का अधिग्रहण किया।

वैश्विक वाणिज्यिक सैटेलाइट इमेजिंग बाजार के बढ़ने के साथ यह पेटेंट भारतीय डीप-टेक की क्षमता को रेखांकित करता है। व्यावसायिक सफलता अब संवेदकों की तैनाती और डेटा सेवाओं की मांग पर निर्भर करेगी।

Hyderabad Startup Hylenr Reports Rare-Earth Signatures in Reactor Tests

Company Says Hydrogen-Loaded Lattice Showed 32 Element Traces; Independent Confirmation Still Needed

Hyderabad: Energy technology startup Hylenr Technologies has reported experimental findings from its hydrogen-based reactor research, saying post-operation samples showed signatures linked to 32 elements, including rare-earth species such as yttrium.

The company presented a paper titled "Nuclear Signatures in a Hydrogen-Loaded Ni-Pd Lattice Confinement System" at the 27th International Conference on Condensed Matter Nuclear Science (ICCF-27) in Niagara Falls, Canada. It said hydrogen-infused nickel-palladium materials produced unusual heat and

changes in gas composition, with higher signals for helium, neon and argon and no matching rise in nitrogen that would suggest air leakage.

Hylenr said elemental signatures were compared with pre-operation baselines of the same catalyst and checked with more than one analytical technique. It described the work as part of a broader programme on lattice confinement and low-energy nuclear reactions. The firm said investigations are continuing to establish the source of the traces and whether they can become a pathway to critical materials.

Rare earths and related elements are strategically important for electronics,

magnets and clean energy. Conventional supply is concentrated and environmentally costly. Any laboratory claim of new production routes therefore attracts attention, but such results require independent replication before they can be treated as a commercial or scientific breakthrough.

Hylenr positions itself as a deep-tech energy company working on hydrogen reactors. Until peer-reviewed validation and third-party tests are published, the findings remain company-reported experimental observations rather than a proven new source of rare earths.

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

- As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
- If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1

Anil Bhardwaj

Technical Head

anil.stockcare@gmail.com

- If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
- Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
- If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
- If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	23398	24437	24163	23781	23507	23125	22851	22469
BANK NIFTY	56605	59172	58300	57452	56580	55732	54860	54012
SENSEX	74782	77852	77165	75973	75286	74094	73407	72215
FINNIFTY	25545	26997	26539	26042	25584	25087	24629	24132
MIDCAP	14585	15269	15016	14800	14547	14331	14078	13862
ACC	1247	1338	1314	1280	1256	1222	1198	1164
AXISBANK	1251	1314	1293	1272	1251	1230	1209	1188
ABCAPITAL	395	417	411	403	397	389	383	375
BHARTIARTL	1841	1903	1880	1860	1837	1817	1794	1774
BHEL	431	457	446	439	428	421	410	403
BIOCON	392	421	413	402	394	383	375	364
BEL	404	431	423	414	406	397	389	380
CDSL	1360	1547	1493	1426	1372	1305	1251	1184
DATAPATTERN	4823	5477	5238	5031	4792	4585	4346	4139
ESCORTS	2895	3139	3088	2991	2940	2843	2792	2695
EICHERMOTOR	7568	7960	7873	7720	7633	7480	7393	7240
FEDERAL BANK	343	356	352	347	343	338	334	329
GRINFRAPROJECT	852	935	914	883	862	831	810	779
HDFCBANK	709	752	732	721	701	690	670	659
HCLTECH	1214	1365	1327	1271	1233	1177	1139	1083
HINDUNILVR	1935	2038	2014	1975	1951	1912	1888	1849
HAL	4917	5326	5212	5064	4950	4802	4688	4540
HYUNDAI	2179	2295	2261	2220	2186	2145	2111	2070
IOC	136	143	141	138	136	133	131	128
ICICIBANK	1382	1487	1461	1421	1395	1355	1329	1289
INFY	1039	1175	1142	1091	1058	1007	974	923
ITC	261	273	270	265	262	257	254	249
KOTAKBNK	418	443	435	426	418	409	401	392
LICHOUSING	564	604	588	576	560	548	532	520
LT	3938	4149	4085	4011	3947	3873	3809	3735
LUPIN	2095	2210	2173	2134	2097	2058	2021	1982
MARUTI	12432	13168	13001	12716	12549	12264	12097	11812
M&M	3115	3281	3230	3172	3121	3063	3012	2954
MGL	1086	1132	1121	1103	1092	1074	1063	1045
MAZGAONDOC	2333	2642	2574	2453	2385	2264	2196	2075
PFC	352	369	364	358	353	347	342	336
RECLTD	314	330	325	320	315	310	305	300
RELIANCE	1263	1378	1351	1307	1280	1236	1209	1165
SBIN	996	1045	1033	1015	1003	985	973	955
SUNPHARMA	1840	1961	1935	1887	1861	1813	1787	1739
SHRIRAMFINANCE	1032	1081	1063	1048	1030	1015	997	982
TITAN	5005	5122	5075	5040	4993	4958	4911	4876
TCS	2208	2390	2345	2276	2231	2162	2117	2048
TATAMOTORS	302	327	319	311	303	295	287	279
UPL	576	605	596	586	577	567	558	548
VALIENT	394	497	445	420	368	343	291	266
WIPRO	167	185	180	174	169	163	158	152

Jio Payment Solutions Launches Cross-Border Payments for Indian

Mumbai: Jio Payment Solutions Ltd, a wholly owned subsidiary of Jio Financial Services, has launched a cross-border payments platform to help Indian exporters collect money from overseas buyers.

The service follows Reserve Bank of India authorisation to operate as a Payment Aggregator for Cross-Border transactions covering both exports and imports. Exporters can accept payments through multi-currency virtual accounts, international cards and local payment rails, reducing reliance on traditional SWIFT and correspondent banking.

The company said the platform is aimed at online sellers, digital businesses, freelancers, SaaS firms and small-to-large enterprises. Merchants can quote prices in local currencies in markets such as the US, UK, Europe, UAE, Singapore, Malaysia and Australia. JPSSL claims coverage of about half of India's export footprint.

Features include T+2 settlement without a rolling reserve, same-day FIRA documentation, encryption and transaction monitoring. JPSSL has partnered with Citi for authorised dealer and export collection account services.

JPSSL already operates as a payment aggregator for online and point-of-sale transactions. The new offering extends its suite to international e-commerce and permitted current account flows.

The launch adds another large domestic player to India's growing cross-border collections market, which has so far been dominated by specialist fintechs and banks. Simpler inbound payments could help smaller exporters compete globally if pricing and compliance support remain competitive.

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.